प्रकाशित: 11 नवंबर 2017 को दैनिक जागरण में प्रकाशित –

गुजरात की राजनीतिक जमीन

डॉ. देवेंद्र कुमार

जुलाई के अंतिम सप्ताह तक राजनीतिक विश्लेषकों में इस पर आम सहमति सी थी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा आसान जीत की ओर बढ़ रही है, लेकिन अक्टूबर आते-आते तमाम विश्लेषकों ने भाजपा की डगर को कठिन घोषित कर दिया। हालंकि अभी तक के सभी जनमत सर्वेक्षणों में भाजपा के पक्ष में बहुमत की भविष्यवाणी हुई है, फिर भी कुछ विश्लेषक गुजरात के विकास में झोल के साथ राहुल गांधी का राजनीतिक पुनर्जन्म होता हुआ देखने लगे हैं। वे भाजपा की डगर कठिन बताने के लिए कांग्रेस के सामाजिक गठबंधन, नोटबंदी और जीएसटी से नाराजगी जैसे कारण गिना रहे हैं। भाजपा की कमजोरी बताए जा रहे इन कथित कारकों की विवेचना आवश्यक है। गुजरात की वर्तमान राजनीति को समझने के लिए उदारवादी खेमे के बुद्धिजीवियों को प्रदेश का चुनावी इतिहास और वोटों के बंटवारे को समझना चाहिए। भाजपा ने पिछले तीन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के मुकाबले दस प्रतिशत मतों की बढ़त के साथ लगभग दो तिहाई बहुमत पाया है। 2014 लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने 27 फीसद मतों की बढ़त बना ली थी। जाहिर है कि कांग्रेस को भाजपा को हराने और सिर्फ साधारण बहुमत पाने के लिए 18 से 20 फीसद मतों की सकारात्मक स्विंग चाहिए। मई 2014 के बाद हुए प्रत्येक चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है। केवल दिल्ली और बिहार में विपक्ष की एकता और मत बंटवारे के समीकरण के चलते उसे मात खानी पड़ी। क्या गुजरात में चंद महीनों में ऐसा कुछ हो गया है कि लगातार हार की मार डोल रही कांग्रेस मतों के अंतर को घटाकर उलटफेर कर सकती है? गुजरात में जातियों की राजनीति करने वाले हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस को समर्थन की तुलना 1980 के दशक के माधव सिंह सोलंकी के 'खाम' समीकरण से की जा रही है, लेकिन ऐसा करते हुए जमीनी हकीकत की अनदेखी की जा रही है।

यह सच है कि आरक्षण के मुद्दे पर हार्दिक पटेल ने लाखों की भीड़ जुटाई है, पर प्रश्न है कि क्या कांग्रेस संविधान के दायरे में रह कर उनको आरक्षण के मुद्दे पर कोई विश्वसनीय आश्वासन दे सकती है? आखिर हार्दिक के लिए लंबे समय से कांग्रेस विरोधी रहे पटेलों का कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटा पाना आसान कैसे होगा? यदि कांग्रेस पटेलों को सैद्धांतिक आश्वासन दे भी देती है तो पिछड़ों की राजनीति करने वाले अल्पेश ठाकोर का कांग्रेस में रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण में 50 फीसद की सीमा के कारण पटेलों को आरक्षण पिछड़ों के हिस्से से ही करनी होगी। ध्यान रहे कि अल्पेश ठाकोर को भाजपा के पिछड़े मतों में सेंध मारने के लिए

नरेंद्र मोदी से भी बड़ा पिछड़ा नेता बनना पड़ेगा। कोली जाति गुजरात की सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है और ठाकोरों को कोली के समकक्ष माना जाता है। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने के कारण कोली समाज में भाजपा के प्रति बढ़े लगाव को भी अल्पेश कमजोर करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। जहां तक जिग्नेश मेवानी का प्रश्न है, वह भी कोई भारी फेरबदल करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में दलित सात फीसद ही हैं और उनका एक बड़ा हिस्सा पहले से ही कांग्रेस के साथ है। आतंरिक विरोधाभास के कारण इन तीनों युवा नेताओं से कांग्रेस की दोस्ती शायद ही उसे कोई लाभ दे पाए।

दो दशकों से अधिक समय से लगातार भाजपा के शासन के कारण उत्पन्न एंटी-इन्कमबैंसी का तर्क देने वाले यह भूल जाते हैं कि राज्य सरकार के काम-काज को दर्शाने वाले संकेतक -सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर गुजरात की जनता को प्रदेश सरकार से कोई शिकायत नहीं है। गुजरात के विकास पर ज्यादा प्रश्न उठाने से यदि गुजरात की अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो गया तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ सकते हैं। इसकी भी अनदेखी न करें कि बाल स्वास्थ्य जैसे विकास सूचकों के आधार पर कांग्रेस द्वारा उछाले गए नारे-विकास पागल हो गया है-की आयु चंद दिन ही रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर विकास को पागल कैसे कहा जा सकता है? आर्थिक सुधार की दृष्टि से एक क्रांतिकारी और अनिवार्य कदम जीएसटी के क्रियान्वयन के शुरुआती दौर में आ रही स्वाभाविक दिक्कतों के कारण निश्चित रूप से समाज के एक वर्ग में नाराजगी है। इसको भुनाने के लिए पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने जीएसटी को एक बड़ा मुद्दा बना रखा है, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए व्यापार जगत से मिल रहे फीड बैक के आधार पर जीएसटी के नियमों में यथोचित सुधार किए हैं। मोदी सरकार के इन कदमों से जीएसटी के कारण उत्पन्न नाराजगी कम हो रही है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी का यह आश्वासन भी भाजपा को राहत देने वाला है कि जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर जीएसटी में सुधार होगा।

गुजरात चुनाव के सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का गुजरात से बाहर रहना भाजपा के खिलाफ जा रहा है। अगर एक क्षण के लिए इस तर्क को सही भी मान लिया जाए तो भी वाघेला के जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कौन नेता है जिस पर गुजरात की जनता विश्वास करेगी? दरअसल मोदी गुजराती गौरव का पर्याय बन गए हैं और प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के लिए दिल्ली आने के बावजूद उन्होंने लगातार गुजरात के विकास में योगदान दिया है। उनके गुजरात में न रहने से गुजराती जनता पर उनके प्रभाव को कम आंकना तर्कसंगत नहीं। इसी तरह अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में भारत की समस्याओं का हल खोजते हुए अचानक ट्विटर के सहारे राहुल गांधी के राजनीतिक पुनर्जन्म की घोषणा में ज्यादा दम नहीं दिखता। ऐसी घोषणाओं की असलियत हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव परिणाम बयान कर देंगे। यदि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की क्षमता पर सचमुच भरोसा होता तो वह गुजरात में उन्हें हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश जैसे रंगरूट नेताओं के पास जाने को नहीं कहती। किसी भी चुनाव में सिर्फ बूथ नियोजन से ही 2 से 3 फीसद मतों के फेरबदल की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। अस्सी के दशक में नरेंद्र मोदी की अगुआई में

गुजरात में भाजपा ने जिस तरह वैज्ञानिक पद्धति से संगठन का विस्तार शुरू किया उसे वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ स्तर पर एक अभेद्य किले का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ पिछले ढाई दशकों में कांग्रेस का जमीनी संगठन लगभग समाप्त हो गया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा लगातार हर जिले में बूथ समिति और 5-7 बूथों के समूह वाले शक्ति केंद्रों की बैठकें लेना भाजपा की अपने संगठन के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। यह संभवत: नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह के संगठन कौशल और गुजरात के विकास के नारे में असर का ही प्रतिफल है कि भाजपा की संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह लगाने वाले कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी करने का साहस नहीं टा पा रहे हैं। ऐसा न करना ही उनकी साख के लिए बेहतर होगा, क्योंकि गुजरात की राजनीतिक जमीन अभी भी भाजपा के लिए अनुकूल दिख रही है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)